RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 06 NOVEMBER TO 12 NOVEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 11 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

व्हॉट्सएप पर ऐसे संपर्कों का चयन किया जा सकेगा, जो प्रयोगकर्ता को किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे
Page 3

प्याज फिर हुआ महंगा
Page 4

BS6 नॉर्म्स लागू होने के बाद 1.6 लीटर डीजल इंजन को फिर लाएगी मारुति
Page 7

editoria!

तसल्ली से हो व्यापार

आरसीईपी यानी 10 आसियान देशों और चीन, भारत, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू जीलैंड के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर फिलहाल टल गया है। बैंकॉक में सभी देशों ने एक स्वर में घोषणा की कि बातचीत पटरी पर है और जो भी थोड़े-बहुत सवाल या संदेह रह गए हैं वे आगे साफ कर लिए जाएंगे। लेकिन जैसे आसार हैं, इस समझौते के लिए निकट भविष्य में इसी तरह का माहौल बनाना आसान नहीं होगा। न केवल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देशों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यह प्रस्तावित समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। दुनिया की आधी आबादी और एक तिहाई से ज्यादा अर्थव्यवस्था को खुद में समेटने की क्षमता इसमें है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भारत और कई अन्य देशों में सस्ते चीनी सामानों की बाढ़ आ जाना है। यह जोखिम अभी के परिवेश में शायद ही कोई उठाना चाहेगा। खतरा सारे देश समझ रहे थे, लेकिन आगे बढ़कर इसे आवाज देने का दम भारत ने ही दिखाया। नवंबर 2012 में इस समझौते पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई थी और पिछले सात वर्षों में सहमति बनाने की कोशिशें चलती रहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर गरमाने के बाद चीन को इस समझौते की जरूरत कुछ ज्यादा ही महसूस होने लगी। इतने बड़े ट्रेड ब्लॉक में शामिल होकर मुक्त व्यापार का फायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा, मगर इससे पहले चीन के साथ भारत के विशाल व्यापार घाटे से जुड़ी चिंताओं का समाधान भी जरूरी है। वैसे भी, इन पड़ोसी देशों से बेरोकटोक माल भारत आने लगे तो हमारे अपने घरेलू उद्योग-धंधे ही नहीं, खेती-किसानी से जुड़ी देश की बहुसंख्यक आबादी का जीवन भी समस्याग्रस्त हो जाएगा। यही वजह है कि इधर कुछ दिनों से देश के अंदर इस समझौते के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर विरोध देखा जा रहा है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार न तो जनभावना से अछूती रह सकती है, न ही अपने राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर सकती है। स्वाभाविक रूप से भारत सरकार ने बैंकॉक बैठक के दौरान जल्दबाजी के लिए बनाए जा रहे दबाव की परवाह न करते हुए अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं और कहा कि आगे बढ़ने से पहले वह इन मसलों पर पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहती है। कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर आयात शुल्क कम करने के लिए भारत तैयार नहीं है। समझौते की हड़बड़ी दिखा रहे चीन और मलयेशिया जैसे देशों को यह पसंद नहीं आया। उनमें से कुछेक ने खुलकर अपनी नापसंदगी भी जाहिर की, लेकिन इस मंच से जुड़े बाकी देश भारत जैसी एशिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था और इसके विशाल बाजार को छोड़ कर आगे बढ़ने में कोई फायदा नहीं देखते। इस समझौते की अहमियत या उपयोगिता से किसी को इनकार नहीं है, मगर इसको कोई ठोस आकार तभी दिया जाना चाहिए, जब यह सबके फायदे में हो और किसी भी देश के लिए कोई नई समस्या न पैदा करे।

RCEP

दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील से क्यों पीछे हटा भारत

जानिए 5 बड़े कारण

नई दिल्ली। एजेंसी

एशिया के 16 प्रमुख देशों के साथ सबसे बड़े व्यापारिक समझौते रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) से भारत पीछे हट गया है। दरअसल, भारत ने इस समझौते से पहले कई मुद्दे और चिंताएं सामने रखी थीं पर उसका ठोस समाधान नहीं निकला। भारत की पहली और सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि चीन समेत इन देशों के साथ पहले से ही बड़ा व्यापार घाटा है। इस समझौते के बाद आयात और ज्यादा बढ़ने की स्थिति में भारतीय उद्योगों और किसानों के हित प्रभावित हो सकते थे। आइए समझते हैं कि भारत की दूसरी चिंताएं क्या हैं और आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। RCEP में आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत और न्यू जीलैंड शामिल हैं। इन देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है और ग्लोबल जीडीपी में इनका 30 प्रतिशत योगदान है। ऐसे में इस समझौते को सबसे बड़ी डील कहा जा रहा है।

पहले समझिए RCEP क्यों

1-RCEP (रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप) की कोशिश दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार ब्लॉक स्थापित करने की है, जिसमें 16 देश होंगे।

2-भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यू जीलैंड 2012 से इस पर बातचीत कर रहे हैं।

3-चर्चा के मुख्य बिंदुओं में 90% सामानों पर आयात शुल्क घटाया जाना या खत्म करना है। चीन के मामले में भारत 80% सामान पर आयात शुल्क शून्य करने के पक्ष में था।

4-इसके अलावा सर्विस, ट्रेड, निवेश बढ़ाना और वीजा नियमों को आसान बनाने पर विचार किया जा रहा था।

भारत ने क्यों बनाई दूरी, 5 बड़े कारण

1. पहले से व्यापार घाटा, और बढ़ने की आशंका

भारत का चीन समेत इन देशों से आयात पहले ही काफी ज्यादा है और निर्यात बेहद कम। ऐसे में आशंका इस बात की है कि इस डील पर हस्ताक्षर करने से चीन से आयात काफी बढ़ जाएगा, जिसमें अन्य RCEP देशों के जरिए सामान की री-रूटिंग शामिल होगी। इससे भारत के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। वित्त वर्ष 2019 में भारत का RCEP देशों के साथ व्यापार घाटा 105 अरब डॉलर है। इसमें से 54 अरब डॉलर का घाटा तो सिर्फ चीन के साथ है। उधर, इस समझौते का भारत में राजनीतिक विरोध भी हो रहा था। भारत में उद्योग और डेयरी फार्मर्स इस व्यापार समझौते का विरोध कर रहे थे। ऐसी आशंकाएं जताई गई थीं कि समझौते में भारत के शामिल होने से चीन से यहां मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और न्यू जीलैंड से डेयरी प्रॉडक्ट्स की डंपिंग होगी, जिससे घरेलू हितों को नुकसान पहुंचेगा। यह भी कहा जा रहा था कि समझौते में भारत के शामिल होने से 'मेक इन इंडिया' अभियान को भी धक्का लगेगा।

2. बेस इयर पर भी भारत की आपत्ति

दूसरे देश 2014 के आधार वर्ष को बदलने के पक्ष में नहीं हैं, जिससे लेटेस्ट व्यापार शुल्क रिफ्लेक्ट हो सके। हालांकि भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी।

3. संरक्षण के मानक नहीं

आयात में बेतहाशा वृद्धि को चेक करने के लिए संरक्षण के कोई मानक नहीं हैं। इससे घरेलू हितों को नुकसान पहुंचेगा, मेक इन इंडिया पर असर पड़ेगा। भारत ने इसको लेकर अपनी चिंता पहले ही जता दी थी पर उसका संतोषजनक समाधान नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में कहा, 'अभी समझौते का जो स्वरूप है वह RCEP के सर्वसम्मत सिद्धांतों और मूल भावना से मेल नहीं खाता।'

4. नॉन-टैरिफ बैरियर्स पर चिंताएं

नॉन-टैरिफ बैरियर्स पर कोई विश्वसनीय प्रतिबद्धता नहीं है। भारत ने आयात शुल्क बढ़ने की स्थिति में सुरक्षा की गारंटी मांगी थी पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। बाजार की पहुंच को लेकर कोई मजबूत भरोसा नहीं मिलना भी बड़ी वजह है।

5. सेवाओं पर ध्यान नहीं

इस डील में सेवाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया जबकि भारत ने इस पर काफी जोर दिया था।

PM ने कहा, नहीं मिला संतोषजनक समाधान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में RCEP सम्मेलन में अपने भाषण में कहा, 'इस समझौते में भारत की चिंताओं और उसकी तरफ से उठाए गए मुद्दों का संतोषजनक समाधान पेश नहीं किया गया है। ऐसे में भारत का RCEP में शामिल होना संभव नहीं है।'

2020 में समझौते पर शुरू होगा काम

RCEP के संयुक्त बयान में कहा गया कि 15 देश 2020 में इस समझौते के लिए औपचारिक स्तर पर काम शुरू करेंगे। इस बीच, उन मसलों को भी सुलझाने की कोशिश होगी, जिनकी तरफ भारत ने ध्यान दिलाया है। बैंकॉक से सोमवार देर शाम जारी बयान में कहा गया, 'समझौते पर भारत का रुख इन मसलों के संतोषजनक समाधान से तय होगा।'

आगे क्या? भारत के नजरिए से समझिए

RCEP सम्मेलन के बाद बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व विजय ठाकुर सिंह ने कहा, 'भारत ने RCEP समझौते का हिस्सा नहीं बनने के अपने निर्णय की जानकारी दे दी है। अभी जो स्थिति है, उसमें समझौते का हिस्सा नहीं बनना ही सही फैसला है।' व्यापार मामलों के एक विशेषज्ञ ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया, 'इस फैसले से भारत के पास अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर विवादित मसलों को सुलझाने की गुंजाइश बन गई है। अब गेंद अन्य देशों के पाले में है। अगर वे हमारी आशंकाएं दूर नहीं कर पाते तो हम इस समझौते का हिस्सा नहीं बनेंगे।'

भारत तेल आयात निर्भरता में 2022 तक 10 प्रतिशत की कमी लाने के रास्ते पर: प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि सरकार 2020 तक तेल आयात पर निर्भरता में 10 प्रतिशत की कमी लाने के रास्ते पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2015 में 'ऊर्जा संगम' में कहा था कि भारत को तेल आयात पर निर्भरता 2013-14 के 77 प्रतिशत के स्तर से घटाकर आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 तक 67 प्रतिशत पर लाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस निर्भरता में 2030 तक आधे की कटौती की जा सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय की पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों के अनुसार हालांकि खपत में तीव्र गति से वृद्धि तथा घरेलू उत्पादन के स्थिर रहने के कारण देश की तेल आयात पर निर्भरता 2018-19 में बढ़कर 83.7 प्रतिशत पर पहुंच गयी जो 2017-18 में 82.9 प्रतिशत थी। एक कार्यक्रम में प्रधान ने संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कहा, ''हम रास्ते पर है। हम लक्ष्य हासिल करेंगे।'' सरकार जैव-ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के साथ कच्चे तेल एवं गैस का घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा आयात कम करने पर ध्यान दे रही है। प्रधान ने कहा कि फिलहाल पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण को बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है और 2022 तक इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही 5,000 कम्प्रेस्ड बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जो फसलों की डंठल , पत्ती और कूड़ा करकट को ईंधन में तब्दील करेंगे। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा वैकल्पिक ईंधन के उपयोग से आयात पर निर्भरता में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये पिछले पांच साल में खोज नियमों में भी बदलाव लाये गये हैं।

इस साल भारत में 52 अरब डॉलर के विलय एवं अधिग्रहण सौदे होने की संभावना: रिपोर्ट

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत में 2019 में 52 अरब डॉलर के विलय एवं अधिग्रहण सौदे होने की संभावना है। बेकर मैकेंजी की एक नयी रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर की अड़चनों के बावजूद भारत में विलय एवं अधिग्रहण सौदों में स्थिरता रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक दिक्कतों के बावजूद भारत में विलय एवं अधिग्रहण बाजार के अगले कुछ साल तक स्थिर रहने की उम्मीद है। ''अनुकूल कारोबारी माहौल के बीच निजी निवेश में सुधार हो रहा है।''आक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के साथ संयुक्त रूप से जारी पांचवी वैश्विक सौदे अनुमान रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019- 22 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात प्रतिशत के करीब रहेगी। इस दौरान वैश्विक स्तर पर जीडीपी की औसत वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है कि 2020 में देश में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) से प्राप्ति घटकर 2.7 अरब डॉलर रह जाने का अनुमान है। वर्ष 2019 में यह करीब 3.4 अरब डॉलर रहेगा। हालांकि, 2021 में आईपीओ से प्राप्ति के बढ़कर 4.3 अरब डॉलर पर पहुंच जाने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में विलय एवं अधिग्रहण बाजार के 2019 में 'सामान्य' स्थिति में पहुंच जाने का अनुमान है। इस दौरान विलय एवं अधिग्रहण सौदे 52.1 अरब डॉलर पर पहुंच सकते हैं।

रक्षा मंत्री ने रूसी रक्षा उद्योग से भारत में संयुक्त रूप से विनिर्माण का अनुरोध किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा उद्योग से भारतीय सैन्य साजो सामान और उपकरणों के विनिर्माण को आधुनिक बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम करने की अपील की। सिंह ने कहा कि इससे दोनों देशों द्वारा अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार 'मेक इन इंडिया' पहल का इस्तेमाल करने के लिए मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) को प्रोत्साहित कर रही है। सिंह रूसी उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मन्तुरोव के साथ 'भारत-रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन' का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने के बाद रूसी रक्षा उद्योग से ओईएम के सीईओ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बड़ी कंपनियों से व्यापार करने को आसान बनाने के लिए किए गए सुधार एवं रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को विदेशी भागीदारों के लिए खोलने के खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का उपयोग करने का अनुरोध किया।

सिंह ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे बनाये हैं और निवेश के लिए आकर्षक शर्तें पेश की हैं। भारत रूस के साथ मिलकर अच्छी गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरणों के मौके तलाशने और सह निर्माण करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम उन्नत और उभरती हुई प्रौद्योगिकी के जरिए अपने रक्षा साजो-सामान को आधुनिक करने के लिए आपका सहयोग चाहते हैं। भारतीय एमएसएमई रूसी और अन्य विदेशी कंपनियों के समर्थन से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पैर जमाना चाहती है। रक्षा मंत्री तीन दिवसीय रूस के दौरे पर हैं, जहां वह सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत-रूस अंतर-सरकारी कमीशन की 19वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। सिंह ने कहा, ''हम जल्द ही रूसी पक्ष के साथ कलपुर्जों और वस्तुओं की सूची साझा करेंगे, जिन्हें भारत में निर्मित करने का प्रस्ताव है। हम निकट भविष्य में समझौते के आधार पर भारत में कई संयुक्त औद्योगिक गतिविधियों को देखने को उत्सुक हैं।'' उन्होंने अगले साल पांच से आठ फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने वाले आगामी रक्षा एक्सपो 2020 में भाग लेने के लिए रूसी निर्माताओं को भी आमंत्रित किया।

एनएसई प्रमुख का वित्त मंत्री से निवेश का प्रवाह बढ़ाने को करों की संख्या घटाने का आग्रह

मुंबई। एजेंसी

देश के शीर्ष शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करों की संख्या में कमी लाने का अनुरोध किया है। एनएसई के प्रमुख विक्रम लिमये ने मंगलवार को कहा कि कई तरह के करों से घरेलू बाजार गैर प्रतिस्पर्धी हो गया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि करों की संख्या में कमी लाकर वह निवेश का प्रवाह बढ़ाने में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि पूंजी बाजार में लेनदेन पर प्रतिभूति लेनदेन कर, पूंजीगत लाभ कर, स्टाम्प शुल्क, माल एवं सेवा कर की वजह से अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार को नुकसान हो रहा है। एनएसई प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जबकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती है और आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर पर आ गई है। हालांकि, सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए हाल में कुछ कदम उठाए है। हाल के दिनों में मीडिया में इस तरह की विरोधाभासी खबरें आई हैं कि क्या सरकार लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति लेनदेन कर और दीर्घावधि के पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करने वाली है। एनएसई की रजत जयंती पर आयोजित समारोह में वित्त मंत्री सीतारमण की उपस्थिति में लिमये ने कहा, ''एक तर्कसंगत कर ढांचे से हमारे बाजारों का आकर्षण उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगा और भागीदारी व्यापक होने से विभिन्न प्रतिभूतियों में तरलता की स्थिति बेहतर हो सकेगी। लिमये ने कहा, ''मैं वित्त मंत्री और सेबी के चेयरमैन से आग्रह करता हूं कि वे कुल लेनदेन लागत की समीक्षा करें। इसमें कर, मार्जिन और अनुपालन की लागत भी शामिल है। इससे भारतीय बाजारों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बेहतर किया जा सकेगा।'' उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक बाजारों में हमारा भारांश भी बढ़ सकेगा जिससे हम अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर सकेंगे।

सरकार ईरान, मिस्र, तुर्की से प्याज आयात को सुविधा प्रदान करेगी, धुंआकरण मानदंड में ढील देगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

खुदरा प्याज कीमतों के आसमान पर चढ़ने के मद्देनजर केंद्र ने मंगलवार को कहा कि वह आयातित प्याज के फ्यूमिगेशन (धूम्र-उपचार) के नियमों में नरमी लाएगी तथा अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान से प्याज के आयात के लिए सुविधा प्रदान करेगा। प्याज के खुदरा भाव 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए है और इसकी आपूर्ति बढाने के लिए सरकार आयात करवा रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। इस बैठक में देश में प्याज की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा की गई। महाराष्ट्र जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के बाद आपूर्ति बाधित होने के कारण दिल्ली और अन्य उपभोक्ता राज्यों के अधिकांश खुदरा बाजारों में पिछले एक महीने से प्याज की कीमतें अधिक बनी हुई हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में प्याज का खुदरा मूल्य मंगलवार को 80 रुपये किलो था, जबकि चेन्नई में 70 रुपये किलो और चेन्नई में 50 रुपये किलो था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, ''आने वाले दिनों में आपूर्ति में सुधार होने की उम्मीद है। केन्द्र सरकार, प्याज के आयात के लिए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेगी। आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए स्वच्छता और धूम्र-उपचार की आवश्यकता को उपयुक्त ढंग से उदार बनाया जायेगा।'' मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्की और ईरान में भारतीय मिशनों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भारत को प्याज की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध करायें। बयान के अनुसार दो अंतर-मंत्रालयीय टीमों को 6-7 नवंबर को कर्नाटक और राजस्थान में भेजा जाएगा ताकि प्याज की आपूर्ति का जायजा लिया जा सके तथा दिल्ली-एनसीआर सहित उपभोगकर्ता क्षेत्रों में आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को कर्नाटक और राजस्थान जाने वाले अधिकारियों की अंतर-मंत्रालयी टीम के साथ जाने की भी सलाह दी गई है। सरकारी उपक्रम, मदर डेयरी के सफल बिक्रीकेन्द्रों के माध्यम से दिल्ली-एनसीआर में 24.90 रुपये प्रति किलोग्राम की सस्ती दर पर केन्द्रीय बफर स्टॉक के प्याज की बिक्री सहित तमाम सरकारी उपायों के बावजूद प्याज की कीमतें अधिक बनी हुई हैं। बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति अन्य राज्यों में भी की जा रही है।

रसायन, पेट्रोरसायन उद्योग को हर कीमत पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा : रसायन सचिव

नयी दिल्ली। देश के रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग को हर कीमत पर पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, फिर चाहे ऐसा करने में कुछ विकास कार्य ही क्यों न प्रभावित हों। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को यह बात कही। भारतीय रसायन परिषद (आईसीसी) द्वारा आयोजित एक निरंतरता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रसायन एवं पेट्रोरसायन सचिव पी राघवेंद्र राव ने कहा, ''यह सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि हम निवेश, वृद्धि और विकास पर जो भी बात करें, उसमें हम कभी इस बात को नहीं भूलें कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाए।''उन्होंने कहा कि उद्योग को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी कीमत पर पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, बेशक इससे वृद्धि और विकास पर कुछ असर क्यों न पड़े। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण पर रसायन सचिव ने कहा कि गैस चैंबर में रहने की स्थिति को हमेशा के लिए कायम नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि सिर्फ पराली की वजह से यह स्थिति नहीं है बल्कि पटाखे जलाने, रसायन और कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। सचिव ने कहा कि यह खेद की बात है कि देश का रसायन एवं पेट्रोरसायन उद्योग दुनिया का छठा सबसे बड़ा उद्योग है लेकिन इसकी हिस्सेदारी मात्र तीन प्रतिशत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस 160 अरब डॉलर के उद्योग की वृद्धि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि से ऊंची है। राव ने कहा कि सरकार पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जल्द ही निवेश आकर्षित करने और इन पीसीपीआईआर को वृद्धि का इंजन बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

आरसीईपी में शामिल नहीं होने का उद्योगों ने किया स्वागत, कहा

घरेलू उद्योग होंगे मजबूत, बढ़ेगा रोजगार

नयी दिल्ली। एजेंसी

आसियान के दस देशों और चीन, जापान, आस्ट्रेलिया सहित 16 देशों के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समूह बनाने वाले क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होने के भारत के फैसले का देश के उद्योग जगत ने खुलकर स्वागत किया है। उद्योग जगत ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी जिससे लाखों लोगों के रोजगार की रक्षा होगी साथ ही अर्थव्यवस्था में जारी सुस्ती का माहौल सुधरेगा। उद्योगों ने कहा कि सरकार का यह निर्णय किसानों, डेयरी कारोबारियों और छोटे उद्योगों के हित में है। एल्यूमीनियम, मशीनी कलपुर्जों, कागज, आटोमोबाइल, रसायन, पेट्रो रसायन और व्यापारिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं होने के कदम को देश और घरेलू उद्योगों के हित में उठाया गया कदम बताया। वाणिज्य एवं उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमानी ने कहा, ''आरसीईपी में शामिल नहीं होने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले का फिक्की पूरी तरह समर्थन करता है। इस समझौते को लेकर अब तक हुई बातचीत में भारत की कई चिंताओं का समाधान नहीं हुआ। कई मुद्दे ज्यों के त्यों रह गये। इस समझौते को लेकर हाल के महीनों में इस्पात, प्लास्टिक, तांबा, एल्यूमीनियम, मशीली कलपुर्जे, कागज, रसायन और पेट्रो रसायन सहित तमाम उद्योगों ने गंभीर आशंका जताई है। एसोचैम अध्यक्ष बी के गोयनका ने कहा कि आरसीईपी से समझौते से बाहर रहने का फैसला प्रधानमंत्री ने काफी सोच समझकर लिया है। इतने बड़े पैमाने पर कई देशों के साथ व्यापार खोलने के मामले में गहन अध्ययन की जरूरत है। पीएचडी वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष डा. डी.के. अग्रवाल ने इस संबंध में जारी वक्तव्य में कहा कि आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं हाने का प्रधानमंत्री का निर्णय भारत के समूचे उद्योग जगत और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों (एमएसएमई) के हित में है। भारत के इस फैसले से एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों में लाखों लोगों के रोजगार की सुरक्षा होगी और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बिठाया जा सकेगा। देश के निर्यातक संगठनों के महासंघ (फियो) अध्यक्ष शरद कुमार सर्राफ ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा कि यदि यह समझौता हो जाता तो चीन की वृहद विनिर्माण क्षमता और तैयार माल के भंडारों से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को तगड़ा झटका लगता और इसका सीधा असर निर्यात कारोबार पर पड़ता। सरकार को देश के विनिर्माण क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये कर्ज, माल लाने ले जाने की लागत कम करनी चाहिये और कर ढांचे में समुचित सुधार लाया जाना चाहिये। व्यापारियों के संगठन कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आरसीईपी समझौते को लेकर सरकार के कड़े रूख को व्यापार एवं उद्योग के हित में बड़ा कदम बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में संगठन ने आरसीईपी के बैंकॉक शिखर सम्मेलन में उनके द्वारा अपनाये गए दृढ रूख की सराहना की है। कैट ने कहा की यह कदम निश्चित रूप से देश में स्वदेशी व्यापार और वाणिज्य को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) ने प्रधानमंत्री के इस मजबूत कदम की सराहना की। एएमएआई का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस एलान से भारतीय अर्थव्यवस्था में बना सुस्ती का माहौल भी सुधरेगा। एएमएआई के अध्यक्ष जयंतीभाई पटेल ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा कि उद्योग पहले से ही सस्ते आयात के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है और घरेलू क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा, 'पिछले व्यापार समझौतों को लेकर हमारा अनुभव बहुत बुरा रहा है, क्योंकि इनसे केवल व्यापार घाटा ही बढ़ता है। पिछले मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) खासकर कोरिया और जापान के साथ हुए एफटीए से भारतीय रसायन उद्योग को आयात में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुंचा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) ने 16 देशों के बीच होने वाले आरसीईपी समझौते से बाहर रहने के भारत के फैसले को ''बुद्धीमत्ता पूर्ण'' कदम बताया। ईईपीसी इंडिया के चेयरमैन रवि सहगल ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो निर्णय लिया है उससे हमारे एमएसएमई क्षेत्र को काफी सहारा मिलेगा। यह उद्योग चीनी आयात मिलने को लेकर काफी आशंकित था। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के संगठन मैट के अध्यक्ष नितीन कुण्कोलिंकर ने फैसले का स्वागत करते हुये इसे ठोस और बेहतर भविष्य के लिये उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत को अब अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत और प्रतिस्पर्धी बनाना चाहिये। भारत को चीन को अपना मुख्य प्रतिस्पर्धी मानकर विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती के लिये काम करना चाहिये। स्कॉच समूह के चेयरमैन समीर कोचर ने कहा कि आरसीईपी पर यदि भारत हस्ताक्षर कर देता तो यह विश्व व्यापार संगठन समझौते से बड़ी गलती होती। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम और भारत को 2030 तक 10 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की सोच के बिल्कुल उलट होता। ''देश को इस नुकसान से बचाने के लिये मैं प्रधानमंत्री मोदी का तहेदिल से धन्यवाद करता हूं।''

सरकार बंदरगाहों के समीप 10 मेगा पार्क बनाने पर कर रही विचार

नयी दिल्ली। सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये बंदरगाहों के पास अत्याधुनिक बुनियादी संरचना वाले करीब १० एकीकृत मेगा पार्क बनाने पर विचार कर रही है। एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।कपड़ा सचिव रवि कपूर ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्तावित मेगा पार्कों को राज्य सरकारों से अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।उन्होंने कहा, जहां तक निर्यात का सवाल है, सभी क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धिता के साथ गंभीर दिक्कतें हैं। चूंकि भारत प्रतिस्पर्धी नहीं है, मुक्त व्यापार समझौतों का भय खुद ही कम हो जाता है।कपूर ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा, ''सरकार देश में मेगा पार्कों पर गंभीरता से काम कर रही है। ये सीमित होंगे, संभवतः १० और ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा करेंगे। आज के समय में जब चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध की बात करें, वे निवेश करने के लिये गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं।''उन्होंने कहा कि एफडीआई आकर्षित करने के लिये विदेशी कंपनियों तथा देश के लोगों को इस तरह की बुनियादी संरचना उपलब्ध करायी जानी चाहिये।

व्हॉट्सएप पर ऐसे संपर्कों का चयन किया जा सकेगा, जो प्रयोगकर्ता को किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे

नयी दिल्ली। एजेंसी

व्हॉट्सएप ने अपने प्रयोगकर्ताओं की निजता के लिए एक नया 'अपडेट' पेश किया है। इसके तहत व्हॉट्सएप के प्रयोगकर्ता ऐसे संपर्कों का चयन कर सकेंगे जो उन्हें किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे। फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने बुधवार को कहा कि यह अपडेट दुनियाभर में प्रयोगकर्ताओं को व्हॉट्सएप के नए संस्करण पर जारी किया जा रहा है। व्हॉट्सएप को इस समय पेगासस स्पाइवेयर की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।। पेगासस स्पाइवेयर के जरिये भारत सहित अन्य देशों में पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी का मामला सामने आया है। व्हॉट्सएप ने एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा है कि शुरुआती स्तर पर इस अपडेट को लेकर

प्रयोगकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद हम 'नोबॉडी' विकल्प के बजाय 'माई कान्टेक्ट्स एक्सेप्ट' का विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं। इसके जरिये प्रयोगकर्ता उन संपर्कों का चयन कर सकते हैं जिनके ग्रुप से आप जुड़ना नहीं चाहते। दुनियाभर में व्हॉट्सएप के प्रयोगकर्ताओं की संख्या डेढ़ अरब है। अकेले भारत में व्हॉट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 40 करोड़ है। व्हॉट्सएप ने अप्रैल में ऐसे नियंत्रण पेश किए थे जिनके जरिये प्रयोगकर्ता यह तय कर सकते हैं कि कौन उनको किसी ग्रुप से जोड़ सकता है। इससे पहले तक व्हॉट्सएप के प्रयोगकर्ताओं को बिना उनकी सहमति के किसी भी ग्रुप से जोड़ा जा सकता था। इस नए फीचर के तहत व्हॉट्सएप पर 'नोबॉडी' के स्थान पर 'माई कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट' का विकल्प होगा। इसमें प्रयोगकर्ता उन संपर्कों का चयन कर सकेंगे जो बिना उनकी सहमति के उन्हें किसी ग्रुप से नहीं जोड़ सकेंगे। अन्य दो विकल्प 'माई कॉन्टैक्ट्स' और 'एवरीवन'कायम रहेंगे।

घर बैठे दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं अपना अकाउंट

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आपका SBI में अकाउंट है तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अब SBI अकाउंट होल्डर्स ऑनलाइन एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में खाता ट्रांसफर कर सकते हैं। किराए के मकान और जॉब ट्रांसफर्स की वजह से आजकल लोगों के घर का पता जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। यही वजह है कि बैंक ने ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर की फैसिलिटी दी है। बता दें कि ब्रांच बदलवाना कई बार जरूरी हो जाता है, हालांकि यह काम काफी पेचीदा होता है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है तो आप घर बैठे यह काम मिनटों में कर सकते हैं। SBI ऑनलाइन ब्रांच बदलने की सुविधा देता है। इस प्रकार आप एसबीआई में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। SBI में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर करने से पहले कुछ जरूरी बातें जाननी चाहिए। इस सुविधा का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं, जिनका अपने बैंक अकाउंट का नो योर क्लाइंट (KYC) अपडेटेड है। इसके अलावा, ऑनलाइन प्रोसेस तभी पूरा हो सकेगा, जब आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से रजिस्टर हो. ऐसा होने के बाद आप आप एसबीआई में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।

बैंक ब्रांच बदलने का प्रोसेस ये है

■सबसे पहले नेट बैंकिंग लॉगिन करें. अपने खाते के होम पेज पर 'ई-सर्विस' के बटन पर क्लिक करें. 'ई-सर्विसेज' सेक्शन में बाईं ओर आप 'बचत खाते के स्थानांतरण' का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर आपको एसबीआई में उपलब्ध खाते दिखाई देंगे। आप जिस खाते को दूसरी शाखा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसे चुनें. और फिर एसबीआई की दूसरी शाखा का ब्रांच कोड डालें।

■फिर 'गेट ब्रांच नेम' टैब को क्लिक करें, इसके बाद शाखा का नाम, उस शाखा का कोड के नीचे दिए गए बॉक्स में दिखेगा. यह कोड वहां से चुन लें। अगर आप पहले से ही शाखा कोड जानते हैं तो उसे भर सकते हैं। 'नियम और शर्तें' पढ़ने के बाद एक्सेप्ट पर टिक करके सबमिट करें।

■सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपको नई शाखा का नाम और कोड दिखेगा। जिसमें आप अपना खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं. पूरी डीटेल्स एक बार जांचें और यदि आपको सब कुछ सही लगे तो कंफर्म बटन पर क्लिक करें।

■इसके बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको डालना होगा। जब आप 'कन्फर्म' पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा।

■इस पर ट्रांसफर कंफर्मेशन मैसेज, आपकी मौजूदा शाखा और उस शाखा का विवरण होगा, जिस पर आपने अपना खाता ट्रांसफर किया है।

कुछ ही दिन में बदल जाएगी ब्रांच

ऐसा होने के बाद आपका एसबीआई में ऑनलाइन बैंक अकाउंट ट्रांसफर का प्रोसेस आपकी तरफ से पूरा हो गया है। इसके बाद एक हफ्ते के अंदर यह नई ब्रांच में पहुंच जाएगा, और आप वहां से बैंकिंग की सभी सुविधाएं ले सकेंगे।

परफॉर्मेंस से तय होगी प्राइवेट बैंकों के CEOs की आधी सैलरी: RBI

कोलकाता। एजेंसी

प्राइवेट सेक्टर बैंकों में 'पे फॉर परफॉर्मेंस' के सिद्धांत के साथ समुचित न्याय हो, इसके लिए उन्हें चीफ एग्जिक्यूटिव्स और होल टाइम डायरेक्टर्स की कम से कम आधी सैलरी उनके इंडिविजुअल और कंपनी लेवल परफॉर्मेंस से जोड़नी होगी। यह बात सोमवार को रिजर्व बैंक ने कही। बैंकिंग रेगुलेटर ने कहा, 'कॉम्पनसेशन का बड़ा हिस्सा यानी कम से कम 50% हिस्सा वेरिएबल के तौर पर रखना होगा और टॉप ऑफिसर्स को इस हिस्से का पेमेंट इंडिविजुअल, बिजनस यूनिट और कंपनी के आधार पर उनके परफॉर्मेंस का समुचित आकलन करने वाले मानकों के हिसाब से करना होगा। इस सिस्टम में मटीरियल रिस्क टेकर्स के अलावा कंट्रोल फंक्शन वाले स्टाफ को भी लाया जाना चाहिए।'

RBI ने कहा है कि जिन रोल्स में ज्यादा रेस्पॉन्सिबलिटी हो उनमें वेरिएबल पे का अनुपात ज्यादा होना चाहिए। इसकी लिमिट फिक्स्ड पे के 300% तक हो सकती है। टॉप एग्जिक्यूटिव्स में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के मकसद से 2012 में वेरिएबल पे को सालाना फिक्स्ड पे के 70% तक लिमिट करने के बाद पहली बार उनके कॉम्पनसेशन रूल्स में बदलाव किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कॉम्पनसेशन को हर तरह के रिस्क के हिसाब से अजस्ट किया जाना चाहिए और कॉम्पनसेशन रिस्क से हासिल होने वाले नतीजों के हिसाब से होना चाहिए। RBI ने पुराने नियमों की समीक्षा इंटरनैशनल लेवल पर अपनाए जाने वाले तौर तरीकों में हो रहे विकास और इन सबके बारे में हासिल अनुभव के आधार पर की है। RBI की कवायद का मकसद मिसकंडक्ट रिस्क घटाने के लिए गाइडलाइंस का अलाइनमेंट करना रहा है।

आरबीआई का कहना है कि बैंक की फाइनैंशल परफॉर्मेंस खराब होने पर होल टाइम डायरेक्टर और मटीरियल रिस्क टेकर्स को उनके टोटल वेरिएबल पे के 60% हिस्से की पेमेंट को न्यूनतम तीन साल के लिए टालना होगा और उसमें क्लॉबैक अरेंजमेंट करना होगा। टॉप एग्जिक्यूटिव्स के कॉम्पनसेशन से जुड़े नए रूल्स 1 अप्रैल 2020 से लोकल एरिया बैंकों, स्मॉल फाइनैंस बैंकों और पेमेंट्स बैंकों सहित सभी प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर लागू होंगे। रेगुलेटर का कहना है कि वेरिएबल पे शेयर लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कैश और शेयर लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के मिक्स के रूप में हो सकते हैं। RBI ने कहा, 'वेरिएबल पे में कैश और शेयर लिंक्ड कंपोनेंट का समुचित संतुलन होना चाहिए। जिन मामलों में शेयर लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए वेरिएबल पे देने की इजाजत नहीं होगी सिर्फ उन्हीं में पूरा वेरिएबल पे कैश में दिया जा सकेगा।'

प्याज फिर हुआ महंगा

बाजारों में भाव 100 रुपये प्रति किलो पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्याज के दामों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिसके तहत इस बार प्याज के दाम बढ़ोतरी के बाद अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फुटकर बाजारों में प्रति किलो 100 रुपये तक बिक रहा है। राजधानी दिल्ली में प्याज के दामों में पिछले कुछ महीनों में यह दूसरी बार बढ़ोतरी है। पूर्व में बरसात से फसर प्रभावित होने की वजह से मंडियों में प्याज की आवाक पर असर पड़ा था। जिससे स्टॉक में आई कमी के बाद दिल्ली के फुटकर बाजारों में 80 रुपये प्रति किलो तक बिका था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल वैन के जरिए 23.90 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज बेचने के लिए योजना शुरू की थी। जिसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल वैन के माध्यम से सस्ती दरों पर प्याज बेचे गए थे, लेकिन इस योजना की समाप्ति के बाद एक फिर प्याज के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। और दिल्ली के विभिन्न फुटकर बाजारों में प्याज 80 से 100 रुपये किलो बिकने लगी है। दिल्ली में प्याज के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर आजादपुर थोक मंडी में प्याज के कारोबारी श्रीकांत ने बताया कि पिछले दिनों मंडियों में प्याज की आवाक में कमी आई थी, इस वजह मंडी में स्टॉक में कमी होने से प्याज के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन एक-दो दिनों से मंडी में राजस्थान से बड़ी मात्रा में प्याज पहुंच रही है। जो 30 से 60 रुपये प्रति किलो के थोक दाम में मंडी आ रही है। अब फिर से प्याज के दामों में गिरावट हो जाएगी और लोगों को बाजार में सस्ती प्याज मिलनी शुरू हो जाएगी।

चीनी मिलों को इथेनॉल उत्पादन के लिए हरित मंजूरी की आवश्यकता नहीं: केन्द्र

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

केंद्र ने घोषणा की कि मिलों को गन्ने के शीरे से अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यह प्रदूषणकारी नहीं है। उसने कहा कि एक कदम से किसानों और नकदी-संकट से जूझ रहे चीनी मिलों को फायदा हो सकता है। किसान को चीनी मिलों से, गन्ना बकाए का भुगतान न किये जाने के कारण गंभीर शिकायत रही है। चीनी मिल मालिकों का कहना है कि चीनी के अत्यधिक उत्पादन और कीमत में गिरावट के कारण, उन्हें भी अपना बकाया नहीं मिल पा रहा है। जून 2019 तक, देश भर के किसानों का चीनी मिलों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये का बकाया है। अतिरिक्त इथेनॉल के उत्पादन को आसान करने से किसानों के बकाए की समस्य कम करने में मदद मिल सकती है। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट किया, ''किसानों और चीनी उद्योग के फायदे के लिए एक और बड़े फैसले के तहत, केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि 'बी' ग्रेड के भारी शीरे से अतिरिक्त इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए कोई अलग से पर्यावरणीय मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है।'' वर्ष 2006 की ईआईए अधिसूचना- सभी नई परियोजनाओं, उनके विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ-साथ उत्पाद मिश्रण में बदलाव करने के लिए, मंजूरी लेने को अनिवार्य बनाता है।

एक्सप्रेस-वे के निकट बनेगा औद्योगिक गलियारा

50 प्रतिशत भूखण्ड एमएसएमई के लिए होंगे आरक्षित

लखनऊ। एजेंसी

उत्तर प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जायेगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को दी गई है। राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने एक बयान में बुधवार को बताया कि यह गलियारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देखण्ड एक्सप्रेस-वे तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों में विकसित हो रहे गलियारे के निकट पांच किलोमीटर की दूरी के अन्तर्गत स्थापित किये जायेंगे। ग्राम सभा की पांच एकड़ से अधिक भूमि एक जगह उपलब्ध होने पर इसको छोटे औद्योगिक परिसर के रूप में विकसित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कि मिनी यानी छोटे औद्योगिक परिसर के विकास के लिये भूमि निःशुल्क उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इस क्षेत्र में 50 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित होंगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि विकसित हो रहे एक्सप्रेस-वे के पांच किमी की परिधि में पांच एकड़ से अधिक ग्राम समाज की अनारक्षित भूमि उपलब्ध होने की दशा में उद्योग विभाग द्वारा प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेजा जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को औद्योगिक परिसर विकसित करने के लिए संबंधित भूमि उद्योग निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। सहगल ने बताया कि औद्योगिक परिसर तथा छोटे औद्योगिक परिसर को विकसित करने संबंधित भूमि के पुनर्ग्रहण के बारे में मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों तथा आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार छोटी इकाइयों, लघु उद्योगों एवं परंपरागत व्यवसायियों को उनके समीप भूमि उपलब्ध कराकर औद्योगीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। इससे ओ.डी.ओ.पी. (एक जिला एक उत्पाद) उद्यमियों को भी पनपने का मौका मिलेगा।

www.eng-expo.co.in
www.eng-expo.in

Why Should You
Participate in Madhya Pradesh ?

- Explore the unexplored opportunities.
- Biggest automobile hub in India.
- Most flourishing food and grain industry.
- Industrial Development on a rapid pace in Plastic Parks, Textile Parks, SEZs, Pharma Zones.
- Both IIMs and IITs are here
- Cleanest city of India third time in a row (IT'S A HATTRICK).
- Fast infrastructure development.
- Centrally connected transport system.
- Good, peaceful and conducive atmosphere for business development.
- Well equipped communication network.
- Proactive initiatives by the state government.

Central India's Largest SME Exhibition

Industrial ENGINEERING EXPO

CONCURRENT EVENTS

3rd International Industry & Technology Expo

PLAST PACK & PRINT EXPO 2019

ELECTRICALS & ELECTRONICS EXPO 2019

INDORE 20 21 22 23 DEC 2019
LABHGANGA EXHIBITION CENTRE

SPONSORED BY

CO-SPONSORED BY

ORGANISED BY

CONCURRENT EVENT ORGANISED BY

SPONSORED BY

SUPPORTED BY

COMPRESSED AIR PARTNER

MEDIA PARTNER

DESIGN PARTNER

BEVERAGE PARTNER

TRANSIT PARTNER

WEB PARTNER

For Participation Call

9826887800, 9826497000, 9981224262, 9827044408

futuretradefairs@gmail.com, industrialenggexpo@gmail.com

क्यों किया जाता है तुलसी विवाह

हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। कहा जाता है जिस घर में तुलसी का पौधा लगा होता है उस घर में हमेशा बरकत होती है और वह घर दुख, दरिद्रता और कलह से परे होता है। धर्म ग्रंथों में तुलसी को हरिप्रिया और आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार तुलसी को संजीवनी बूटी भी कहा गया है, क्योंकि तुलसी के पौधे में अनेकों औषधीय गुण होते हैं। तुलसी के औषधीय गुण तो हैं ही, साथ ही तुलसी दैवीय शक्ति के रूप में घर-घर पूजी जाती हैं।

भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक, शुक्ल पक्ष, नवमी की तिथि ठीक होती है। परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर पांचवें दिन तुलसी विवाह करते हैं।

इस दिन को देवप्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस मांगलिक पर्व के सुअवसर पर शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें साक्षात् नारायण स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि-विधानपूर्वक उनके विवाह को सम्पन्न कराते हैं।

पौराणिक कथानुसार भगवान विष्णु को चार मास की योग निद्रा से जगाने के लिए घंटा, शंख, मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि के साथ यह श्लोक पढ़कर जगाया जाता है-

'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यजनिद्रांजगत्पते।
त्वयिसुप्तेजगन्नाथ जगत् सुप्तमिंदभवेत्।।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठवाराह दंष्ट वेद्वत वसुंधरे।
हिरण्याक्षप्राणघातिन्त्रैलोक्येमंगलम्कुरू।।'

यदि संस्कृत में इस श्लोक को पढ़ने में कठिनाई हो तो-उठो देवा, बैठो देवा कहकर श्रीनारायण को उठाया जाता है।

कैसे मनाया जाता है

तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है-तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान। मंडप, वरपूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रीतिभोज सब कुछ पारम्परिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और तुलसी कन्या की भूमिका में होती हैं। तुलसी विवाह में सोलह श्रृंगार के सभी सामान चढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। इस दिन तुलसी पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है। तुलसी विवाह के पश्चात् प्रीतिभोज का आयोजन किया जाता है।

कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां भी कार्तिक शुल्क एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं और गीत तथा भजन गाती हैं।

भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है।

प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा ही वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था, उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्वविजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा करने की गुहार की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने काफी सोच-विचार कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योगमाया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फिंकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति का नजर आया।

अपने पति को मृत देखकर, वह उस मृत शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, ''बेटी इतना विलाप मत करो। मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी।'' भावातिरेक में वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया जिसके कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल-कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया।

जब वृंदा को इस बात का पता चला तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, ''जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छलपूर्वक हरण होने पर स्त्री-वियोग सहने के लिए मृत्यु-लोक में जन्म लोगे।''

यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए।

देवताओं और ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती ने वृंदा की चिता-भस्म में आंवला, मालती और तुलसी के पौधे लगाए।

भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा मगर कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं-कहीं प्रचलित है कि वृंदा ने यह शाप दिया था-तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है। अतः तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले वृंदा तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, वह परमधाम को प्राप्त होगा। इसी कारण बिना तुलसी दल के शालीग्राम यानी विष्णु-शिला की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि से भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह सम्पन्न करता है।

सर्व सुखदायक हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत

दीपोत्सव के ग्यारह दिन बाद आने वाली एकादशी को हरिप्रबोधनी एवं देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत से प्राप्त की जा सकती है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को चार माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। चार माह बाद वे कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। 'भगवान पुराण' के अनुसार विष्णु के शयनकाल के चार माह में मांगलिक कार्यों का आयोजन निषेध है।

'आदि पुराण' के अनुसार एकादशी तिथि का उपवास बुद्धि और शांति प्रदाता व संततिदायक है। 'विष्णु पुराण' के अनुसार किसी भी कारण से चाहे लोभ के वशीभूत होकर जो एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का अभिनंदन करते हैं, वे समस्त दुखों से मुक्त होकर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सनत् कुमार ने लिखा जो व्यक्ति एकादशी व्रत या स्तुति नहीं करता वह नरक का भोगी होता है। महर्षि कात्यायन के अनुसार जो व्यक्ति संतति, सुख सम्पदा, धन-धान्य व मुक्ति चाहता है तो उसे हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु स्तुति, शालिग्राम व तुलसी महिमा का पाठ करना चाहिए व व्रत रखना चाहिए।

ब्रह्मा जो हिन्दू धर्म में प्रमुख देवता हैं, उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। मनुष्य को जो फल एक हजार अश्वमेध और एक सौ राजसूय यज्ञों से मिलता है, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है।

ब्रह्मा जो हिन्दू धर्म में प्रमुख देवता हैं, उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। मनुष्य को जो फल एक हजार अश्वमेध और एक सौ राजसूय यज्ञों से मिलता है, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से मिलता है।

नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ने उपवास बारे जानना चाहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरू और मंदराचल के समान भारी पाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षणभर में भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार रूई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी-सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधिपूर्वक किया थोड़ा-सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, परस्त्री गमन करने वाले ये सब पापात्मा हैं। जो इस एकादशी के व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण से उनकी आने वाली पीढ़ियां स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता से सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो फल भूमिदान करने से होता है वही फल इस एकादशी की रात्रि जागरण से मिलता है। यह एकादशी विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बतलाने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। मन, कर्म, वचन से जो भी पाप हो जाए इस एकादशी के रात्रि जागरण से नष्ट हो जाते हैं।

इस एकादशी के रात्रि जागरण से चंद्र, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से हजार गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते या सुनते हैं उनको 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। प्रस्तुति : कृष्ण पाल छाबड़ा, गोधरा

BS6 नॉर्म्स लागू होने के बाद 1.6 लीटर डीजल इंजन को फिर लाएगी मारुति

नई दिल्ली।एजेंसी

भारत में अगले साल अप्रैल के महीने से बीएस6 नॉर्म्स लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में मारुति इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले अपनी कारों में डीजल इंजन नहीं देने की घोषणा की थी। हालांकि, कंपनी ने ये भी बताया था कि वो अपनी कुछ बड़ी कारों में बीएस6 नॉर्म्स के अनुसार अपग्रेड डीजल इंजन दे सकती है। हाल ही में 1.6 लीटर बीएस6 इंजन से लैस मारुति एस-क्रॉस को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2020 में मारुति फिर से अपनी कुछ कारों में 1.6 लीटर डीजल इंजन दे सकती है।

जानकारी के मुताबिक, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की मारुति एस-क्रॉस को सबसे पहले नेक्सा डीलरशिप के जरिये बेचा गया था। इस कार में फिएट से लिए गए 1.3 और 1.6 लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है। एस-क्रॉस का 1.6 लीटर इंजन वाला वेरिएंट केवल 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स में ही उपलब्ध था। यह इंजन 120 पीएस की पावर और 320 एनएम का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। एस-क्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को पेश करने के साथ कंपनी ने अपने टार्गेट कस्टमर को आकर्षित करने के लिए 1.6 लीटर इंजन वाले महंगे वेरिएंट को ही बंद कर दिया।

टेस्टिंग के दौरान नज़र आई एस-क्रॉस फेसलिफ्ट पर 1.6 की बैजिंग भी दिखाई दी है। माना जा रहा है कि मारुति इस कार के साथ 1.6 लीटर डीज़ल इंजन को फिर से पेश करने जा रही है। यह इंजन बीएस6 नॉर्म्स के अनुसार अपग्रेड होगा। कंपनी इसे सियाज़ और एक्सएल6 जैसी कारों में भी दे सकती है। माना ये भी जा रहा है कि कंपनी 2018 सियाज़ फेसलिफ्ट के साथ पेश किए गए 1.5 लीटर डीज़ल इंजन को अप्रेल 2020 से पहले बंद कर सकती है।

मारुति स्विफ्ट, विटारा ब्रेज़ा, डिज़ायर और बलेनो जैसी छोटी कारों में दिए गए 1.3 लीटर डीज़ल इंजन को भी बंद कर सकती है। इसके बाद इन कारों में केवल पेट्रोल इंजन का ही एकमात्र विकल्प मिलेगा। वर्तमान में मारुति एस-क्रॉस माइल्ड हायब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.3 लीटर डीज़ल इंजन में ही उपलब्ध है। एस-क्रॉस की प्राइस 8.81 लाख रुपये से शुरू होती है जो 11.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक पहुंचती है। मारुति द्वारा 2020 ऑटो एक्सपो में एस-क्रॉस का बीएस6 पेट्रोल इंजन वाला वर्जन भी पेश कर सकती है।

वाहन को कबाड़ करने की इकाई लगाएंगी मारुति, टोयोटा सुशो, जगह नोएडा में होगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

मारुति सुजुकी और टोयोटा सुशो समूह ने संयुक्त उद्यम बनाने की घोषणा की है। यह संयुक्त उद्यम वाहन को कबाड़ बनाने और उसका पुनर्चक्रण यानी रिसाइक्लिंग करने की इकाई स्थापित करेगा। इस संयुक्त उद्यम मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लि.(एमएसटीआई) में मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत की होगी। शेष 50 प्रतिशत हिस्सेदारी टोयोटा सुशो समूह की कंपनियों....टोयोटा सुशो कॉरपोरेशन और टोयोटा सुशो इंडिया प्राइवेट लि. के पास रहेगी। दोनों कंपनियों ने संयुक्त बयान में कहा कि एमएसटीआई 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश के नोएडा में वाहन को कबाड़ और रिसाइकिल करने का कारखाना लगाएगी। बयान में कहा गया है कि देश के अन्य हिस्सों में इस तरह की इकाइयां लगाई जाएंगी। यह इकाई मियाद की अवधि पूरी कर चुके वाहनों को कबाड़ या स्क्रैप में बदलेगी। बयान में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में भारतीय कानूनों और वैश्विक स्तर पर मान्य गुणवत्ता तथा पर्यावरण मानदंडों के तहत ठोस एवं तरल कचरे के पूर्ण प्रबंधन शामिल होगा। शुरुआत में नोएडा इकाई की क्षमता प्रति माह 2,000 वाहनों को कबाड़ करने की होगी। एमएसटीआई डीलरों के अलावा सीधे ग्राहकों से वाहन हासिल करेगी।

पलूशन से बचाने के लिए स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दे रहीं कंपनियां

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए स्वीडिश फैशन रिटेलर ए ऐंड श, कोका-कोला, केएफसी और डाबर जैसी कंपनियों ने स्टाफ को राहत देने का कदम बढ़ा दिया है। इसके तहत वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने या उन्हें उनकी सुविधानुसार वर्क टाइमिंग जैसे विकल्प दे रही हैं।

'घर पर ही रहकर करें काम'

रविवार को ए ऐंड श ने अपने दिल्ली ऑफिस के कर्मचारियों को ईमेल भेजकर कहा था कि उन्हें सोमवार को घर रहकर ही काम करना चाहिए। कंपनी ने कहा था कि वे 15 नंबबर तक मंगलवार के दिन जल्दी ऑफिस जल्दी आ सकते हैं या घर जल्दी जा सकते हैं। स्टोर के एंप्लॉयीज को 15 नवंबर तक अतिरिक्त ब्रेक लेने के लिए भी कहा गया है। एक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह-सुबह पीक पलूशन वाले घंटों से बचने के लिए जिन स्टोर्स पर मुमकिन होगा, वहां पहली शिफ्ट 8 बजे के बाद से शुरू करने का फैसला किया गया है। वहीं, बेवेरेज मेकर कोका-कोला ने भी अपने स्टाफ को एक हफ्ते के लिए घर से काम करने या फ्लेक्सिबल टाइमिंग जैसे विकल्प देने का निर्णय किया है।मेन्यू 'डीटॉक्सिफाइंग'

डीएलएफ गोल्ड ऐंड कंट्री क्लब अभी पर्यटन मंत्रालय की ओर से प्रमोटेड बिजनस ऑफ गोल्फ पर एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस-एशिया पसिफिक गोल्फ समिट होस्ट कर रही है। उसने इस समिट के लिए प्लान बी के तहत कई विकल्प तैयार किए हैं। इसके तहत कंपनी ने मेन्यू 'डीटॉक्सिफाइंग' करने के अलावा पूरे समिट के लिए सभी ऐक्टिविटीज को इनडोर में शिफ्ट कर दिया था। साथ ही समिट हॉल में दर्जनभर एअर प्यूरिफाइंग मशीन भी लगा दी गई थीं। डीएलएफ गोल्फ रिजॉर्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशंस) विशाल भारती ने कहा, 'प्रतिनिधियों की सेहत हमारी प्राथमिकता है और इसे ही ध्यान में रख कर ये कदम उठाए गए हैं।'

कारपूल ऐप

इन कंपनियों के अलावा फास्ट फूड रेस्टॉरेंट चेन केएफसी की स्थानीय इकाई ने अपने एम्प्लॉयीज को 6 नवंबर तक वर्क फ्राम होम की सुविधा दी है। पैकेज्ड कन्ज्यूमर गुड्स बनाने वाली डाबर के एचआर एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर वी कृष्णन ने कहा कि कंपनी ने प्रदूषण घटाने और कार्बन एमिशन कम करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत कंपनी ने रोजाना आने-जाने की योजना बनाने के लिए कलीग्स को एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कारपूल ऐप लॉन्च किया है।

एंप्लॉयीज को दिए मास्क

मैगी नूडल्स और नेस्कैफे कॉफी बनाने वाली गुरुग्राम स्थित पैकेज्ड फूड्स कंपनी नेस्ले ने फील्ड पर काम करने वाले एंप्लॉयीज को मास्क मुहैया कराए हैं। इसके साथ ही वह कंपनी के डॉक्टर के साथ एक जागरूकता सत्र भी आयोजित करने जा रही है। डाबर भी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम विकल्प देने पर विचार कर रही है। एक प्रवक्ता ने कहा, 'हमने एअर प्यूरिफायर्स भी इंस्टॉल किए हैं। कार-पूलिंग भी शुरू की है।'

ई-वाहन चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर जोर-शोर से चल रहा काम: एनटीपीसी

नयी दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी इलेक्ट्रिक वाहनों (ई - वाहन) के चार्जिंग बुनियादी ढांचे पर काम कर रही है। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक मोहित भार्गव ने कहा कि ई - वाहन एक अच्छा विचार या परिकल्पना है लेकिन बैटरी से जुड़ी चीजें एक अहम मुद्दा है। भार्गव ने भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा , ' एनटीपीसी ई - वाहन के मोर्चे पर दृढ़ता के साथ काम कर रही है। खासकर चार्जिंग नेटवर्क के मामले में। ' उन्होंने कहा , ' बैटरी को लेकर कई बड़ी दिक्कतें हैं ... जैसे बैटरी के चलने की अवधि और बैटरी का फिर से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। '

बीएसएनएल, एमटीएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) ने अपने कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है। कंपनी को उम्मीद है कि इस योजना का लाभ 70,000 से 80,000 कर्मचारी उठाएंगे और इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। सरकार के इस दूरसंचार कंपनी के लिये राहत पैकेज की मंजूरी के कुछ दिनों बाद वीआरएस लायी गयी है। बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने पीटीआई भाषा से कहा कि योजना चार नवंबर से तीन दिसंबर तक खुली रहेगी। वीआरएस की पेशकश के बारे में कर्मचारियों को जानकारी देने के लिये क्षेत्रीय इकाइयों को इस बारे में निर्देश दिये जा चुके है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख है और करीब एक लाख कर्मचारी इस योजना के लिये पात्र हैं। पुरवार ने कहा, ''यह सरकार द्वारा दी गयी बेहतर वीआरएस योजना है और बीएसएनएल कर्मचारियों को इसे सकारात्मक रुप से देखना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि 70,000 से 80,000 कर्मचारियों के इस योजना का विकल्प चुनने की उम्मीद है। इस हिसाब से वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ रुपये की बचत की उम्मीद है। बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 के अनुसार 50 साल की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक उम्र के बीएसएनएल के सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी वीआरएस के लिये आवेदन देने को पात्र हैं। इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएसएनएल के बाहर दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं। पात्र कर्मचारी के लिये अनुग्रह राशि पूरे किये गये प्रत्येक सेवा वर्ष के एवज में 35 दिन तथा बची हुई सेवा अवधि के लिये 25 दिन के वेतन के बराबर होगी। महानगर टेलीफोन निगम लि. (एमटीएनएल) ने भी अपने कर्मचारियों के लिये वीआरएस लागू की है। कर्मचारियों के लिये यह योजना तीन दिसंबर तक के लिये है। हाल में एमटीएनएल द्वारा कर्मचारियों को जारी नोटिस में कहा गया है, ''सभी नियमित और स्थायी कर्मचारी जो 31 जनवरी 2020 तक 50 साल पूरे कर लेंगे या उससे अधिक उम्र के होंगे, वे योजना के लिये पात्र होंगे। सरकार ने पिछले महीने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिये 69,000 करोड़ रुपये के पुनरूद्धार पैकेज की घोषणा की थी। इसमें घाटे में चल रही दोनों सरकारी दूरसंचार कंपनियों का विलय, उनकी संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाना तथा कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है। इस कदम का मकसद विलय बाद की इकाई को दो साल में लाभ में लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के विलय को मंजूरी दी। एमटीएनएल मुंबई और नयी दिल्ली में सेवा देती है जबकि बीएसएनएल देश के अन्य भागों में सेवा देती है।

अगर हमारी चिंताओं का समाधान होता है, भारत आरसीईपी देशों के साथ बातचीत को लेकर तैयार: गोयल

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को संकेत दिया कि अगर आरसीईपी के सदस्य देश चिंताओं को दूर कर और घरेलू उद्योग के लिये बेहतर बाजार पहुंच के साथ अच्छी पेशकश लाते हैं तो भारत बातचीत के लिये तैयार है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी सरकार का निर्णय अंतिम है कि भारत चीन समर्थित वृहत व्यापार समझौता...क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते में शामिल नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बैंकाक में कहा कि भारत आरसीईपी समझौते में शामिल नहीं होगा क्योंकि बातचीत हमारे मसलों और चिंताओं को समाधान करने में विफल रही है। आरसीईपी में 16 सदस्य देश शामिल हैं। इसमें आसियान के 10 सदस्य देश तथा भारत समेत छह कारोबारी भागीदार हैं। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''फिलहाल यह अंतिम निर्णय है। हम आरसीईपी से नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मांगें मानी जाती है, भारतीय उद्योग को वृद्धि के लिये और अवसर मिलते हैं, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना बाजार पहुंच बढ़ता है..तो मुझे लगता है कि हर सरकार बातचीत के लिये तैयार होगी।'' उन्होंने कहा,''अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिविधियों और संबंधों के रास्ते किसी के लिये भी कभी बंद नहीं होते..अगर वे हमारी चिंताओं को दूर करने के लिये ईमानदार प्रयास करते हैं, हमें भरोसा देते हैं और व्यापार असमानता को संतुलित करने में हमारी मदद करते हैं, तब मुझे लगता है कि किसी भी देश को अपने मित्रों से बातचीत करनी चाहिए। हम किसी के साथ कोई दुश्मनी करके नहीं बैठे हैं।'' भारत ने चीन जैसे देशों के साथ बढ़ते व्यापार घाटा, वस्तुओं के आयात में अचानक से वृद्धि या डंपिंग को रोकने के लिये प्रणाली, शुल्क में कटौती के लिये आधार वर्ष 2014 की जगह 2019 किये जाने जैसे मामलों को लेकर आरसीईपी में कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं से यह सबक मिली है कि किसी को समयसीमा के साथ जल्दबाजी में व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं देना चाहिए जैसा कि 2010-11 में जापान, कोरिया और आसियान के साथ समझौते किये गये। उन्होंने कहा, ''व्यापार वार्ताओं में पर्याप्त समय मिलना चाहिए ताकि लोगों और देश के हितों को सावधानीपूर्वक ध्यान रखा जाए।'' यह पूछे जाने पर कि क्या भारत ने अंतिम मिनट में समझौते को तोड़ने वाला बना, गोयल ने कहा कि देश इन मसलों को 2014 से उठा रहा है और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये अपने रुख पर कायम है। मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अफसोस जताया कि कांग्रेस ने जापान, कोरिया, आसियान और मलेशिया के साथ ये समझौते जल्दबाजी में किये। इन समझौतों में भारत को उन उत्पादों के लिये बाजार पहुंच नहीं मिली जहां उसे प्रतिस्पर्धी लाभ था। प्रधानमंत्री द्वारा इन मुद्दों को उठाये जाने के बाद आसियान समीक्षा के लिये अब तैयार है। कोरिया भी तैयार है। हमने भी शुरू किया है। जापान भी इसके लिये तैयार है।'' मंत्री ने सरकार की आलोचना को लेकर कांग्रेस पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह मनमोहन सिंह सरकार थी जिसने भारत को आरसीईपी समूह में शामिल होने को लेकर चर्चा की शुरूआत की थी और इस बात की अनदेखी की थी कि सदस्य देशों के साथ उसका बड़ा व्यापार घाटा है। आरसीईपी समूह के साथ व्यापार घाटा 2004 में 7 अबर डॉलर था जो 2014 में बढ़कर 78 अरब डॉलर पहुंच गया।

आर्थिक सुधारों का अगला दौर जल्द, अब नहीं होगी देर: निर्मला सीतारमन

मुंबई। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को कहा कि सरकार उसे मिले मजबूत जनादेश का इस्तेमाल जल्द ही आर्थिक सुधारों के नए दौर को आगे बढ़ाने के लिए करेगी और इस बार देर नहीं की जाएगी। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में अहम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के असफल प्रयासों का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पिछली बार राज्यसभा में सत्ता पक्ष की कमजोर संख्या की वजह से प्रयास सफल नहीं हो पाए थे। गौरतलब है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण सहित कुछ अन्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रयास सफल नहीं हो पाए थे।

कई जानकारों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को सुस्ती के मौजूदा दौर से बाहर निकालने के लिए भूमि और श्रम कानूनों के क्षेत्र में सरकार की ओर से सुधारों को आगे बढ़ाने के तुरंत प्रयास किए जाने चाहिए। सरकार के पास इस समय मजबूत जनादेश उपलब्ध है। एक अखबार के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि अब हम अपनी इस प्रतिबद्धता को दिखा सकते हैं कि सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इस मामले में मोदी-2.0 को मिला जनादेश मदद मर सकता है।' वित्त मंत्री ने कहा, 'हम उन सुधारों को आगे बढ़ाएंगे जिन्हें पिछली बार पूरा नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस बार इसमें देरी नहीं होगी।'

वित्त मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारतीय जनता पार्टी हाल में हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं ला पाई। हालांकि, इस दौरान पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों को काफी जोरशोर से उठाया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि गहराते कृषि संकट और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे राष्ट्रीयता कार्ड पर हावी रहे। सीतारमण से जब यह पूछा गया कि हाल के विधानसभा चुनावों में क्या आर्थिक मुद्दे राजनीति पर हावी रहे? जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल, विशेषकर जो दल सत्ता में रहता है उसके लिए किसी मुद्दे को अलग रखना संभव नहीं होता है।

उन्होंने कहा, 'किसी भी सरकार के लिये चाहे वह केन्द्र की हो या फिर राज्य की हो, मतदाताओं से यह कहना संभव नहीं है कि राष्ट्रीयता पर आप अपना मत मुझे दीजिए और मैं आर्थिक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता हूं। क्या मतदाता भी इतना दयालु हो सकता है कि ठीक है कि प्रधानमंत्री अर्थव्यवस्था को लेकर बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है हम भी अर्थव्यवस्था पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं।' वित्त मंत्री ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा अभी भी कुछ बाहरी कारकों जैसे कि जमीन, बिजली की ऊंची लागत और भू-उपयोग में बदलाव जैसे मुद्दों से कमजोर पड़ी है। ये मामले ऐसे हैं जो कि किसी एक कंपनी के दायरे से बाहर के हैं। लेकिन सरकार इन मामलों को सुगम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, 'कारोबार सुगमता को वास्तव में हासिल करने के लिए कई चीजों के मामले में अभी लंबा रास्ता तय किया जाना है।'

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध से भारत ने 75.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निर्यात किया: अंकटाड

संयुक्त राष्ट्र। एजेंसी

अमेरिका - चीन व्यापार युद्ध से भारत को व्यापार मोर्चे पर फायदा पहुंचा है। भारत ने 2019 की पहली छमाही में अमेरिका को 75.5 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त निर्यात किया है। यह निर्यात विशेषकर रसायन , धातु और अयस्क में हुआ है। संयुक्तराष्ट्र व्यापार एवं निवेश निकाय अंकटाड ने एक अध्ययन में यह बात कही। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध से द्विपक्षीय व्यापार में तेज गिरावट , उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ना और व्यापार युद्ध से सीधे तौर पर नहीं जुड़े देशों से आयात बढ़ा है। अध्ययन में कहा गया है कि अमेरिका - चीन व्यापार युद्ध से 2019 की पहली छमाही में करीब 21 अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित हुआ है। चीन के उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क ने अन्य देशों को अमेरिकी बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है और इससे इन देशों का अमेरिका को व्यापार बढ़ा है। ताइवान , मेक्सिको और यूरोपीय संघ को इसका काफी लाभ हुआ है। अंकटाड ने कहा , ' कोरिया , कनाडा और भारत को व्यापार में कम लाभ हुआ है लेकिन फिर भी यह पर्याप्त है। ' संयुक्त राष्ट्र निकाय ने बताया कि चीन पर अमेरिकी शुल्क से भारत के 2019 की पहली छमाही में अमेरिका को अतिरिक्त निर्यात करने से 75.5 करोड़ डॉलर मिले हैं। भारत ने अधिक रसायनों (24.3 करोड़ डॉलर), धातु एवं अयस्क (18.1 करोड़ डॉलर), इलेक्ट्रिकल मशीनरी (8.3 करोड़ डालर) और विभिन्न मशीनरी (6.8 करोड़ डॉलर) की बिक्री करके यह लाभ कमाया है। इसके अलावा कृषि - खाद्य उत्पाद , फर्नीचर , वस्त्र एवं परिधान और परिवहन उपकरणों का निर्यात भी बढ़ा है।

एसोसिसएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी की प्रतियोगिता संपन्न

श्री वैष्णव युनिवर्सिटी में हुए खेल और सांस्कृति आयोजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश की सभी युनिवर्सिटी का सबसे बडा संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी द्वारा इंदौर में खेल प्रतियोगता का आयोजन इंदौर में किया। इसके साथ ही सांस्कृति और शैक्षणिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। वर्ष 1925 में स्थापित इस संगठन को 1967 से सोसायटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रति वर्ष होने वाले इस आयोजन के वेस्ट झोन के आयोजन इंदौर में आयोजित किए गए।

श्री वैष्णव विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री उपेंद्र धर ने बताया कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी द्वारा प्रतिवर्ष खेल प्रतियोगिता के साथ ही शैक्षणिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते है। यह कार्यक्रम छात्रों को खेल और संस्कृति से जोड़ने के लिए किए जाते है। इंदौर में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में 68 टीम ने भाग लिया। इसमें 7 राज्यों के खिलाडी शामिल थे। आयोजन को बहुत की अच्छा रिपांस मिला। श्री धर ने बताया कि खेल प्रतियोगिता के 4 झोन के आयोजन संपन्न होने के बाद फाइनल होगा।

इंदौर में सब जुनियर हैंडबाल प्रतियोगिता संपन्न

कार्यकारी अध्यक्ष मनोज मनु भी हुए शामिल

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

शहर के एमराल्ड हाइट्स स्कूल के इनडोर स्टेडियम में नेशनल सब जुनियर बायज हैंडबाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 1 से 5 नवंबर तक मुकाबले खेले गए। आयोजन में कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज मनु, प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी, हैंडबाल फेडरेशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडे, मप्र ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रमेश मैंदौला, विधायक विशाल पटेल भी शामिल हुए।

फेडरेशन के सचिव प्रितपाल सिंह सलुजा ने बताया कि इस आयोजन में साई नेशनल हैंडबाल एकेडमी सहित 33 टीमों ने भाग लिया है। जो कि अभी तक के किसी भी आयोजन का रिकार्ड है। उन्होने बताया कि यह आयोजन इंदौर में पहलीबार आयोजित किया गया। इसमें देश के कौने- कौने से बच्चे भाग ले रहे है। आयोजन में अतिथियों ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए परिचय प्राप्त किया और वितेजा टीमों को पुरूस्कार भी प्रदान किए। इस दौरान बडी संख्या में स्कूली छात्र और दर्शक मौजूद थे।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित । संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।